HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

No. C/3041 Jabalpur, dated 30.6.2022

Copy of the notification of the Government of M.P. F.No.2423/21-B(1)/2022; issued as per the provisions of Section 3(1) of the Prevention of Corruption Act; 1988, Section 14(1) of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act; 1989 and Sections 6(1) & 6(1-A) of the Madhya Pradesh Dacoity and Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable the Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges; all in the State. The Principal District and Sessions Judges, Indore, Bhopal, Gwalior and Jabalpur are also requested to notify the same to the Judges working in their kind control;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. The Registrar (Judicial-1), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Joint Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information.

30.6.2022

(VIVEK SAXENA)
REGISTRAR District Establishment

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,
अधिसूचना

भोपाल दिनांक 29/06/2022

फा.क्र. 2423/21–ब(एक)/2022 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरूद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 के पालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, की धारा 3 की उप–धारा (1) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 की उप–धारा (1) एवं मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा 6 की उप–धारा (1) तथा उप–धारा (1–क) के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के आसीन एवं पूर्ववर्ती संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता हैं, जिनका मुख्यालय उसके सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थान पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी।

सारणी

क्र.	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय के स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मुकेश नाथ, बाइसवें, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर	इंदौर	इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, अलीराजपुर, नीमच, शाजापुर मंदसौर एवं देवास।
2	श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, इक्कीसवें, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, राजगढ़, सागर, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा।
3	श्री सुशील कुमार जोशी, अष्टम, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी।
4	श्री विवेक पटेल, इक्कीसवें, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, अनुपपुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोह एवं सीधी।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

Notification

F.No. 2423 /21-B(1)/2022, In compliance of the order passed on 14-12-2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwani Kumar Upadhayay vs. Union of India & Others, as per the provisions of sub-section (1) of Section 3 of Prevention of Corruption Act, 1988, sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and sub-section (1) and sub-section (1-A) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dacoity Avam Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981, the Government of Madhya Pradesh in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court(s) of Additional Sessions Judge(s) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act, 1988, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Madhya Pradesh Dacoity Avam Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 against the sitting and former Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh specified in Column (2) of the table below having Headquarters at places, specified in column (3) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts specified in column (4) thereof.

TABLE

S.N.	Name of Special Court	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Mukesh Nath, XXII ASJ, Indore	Indore	Indore, Ujjain, Dhar, Jhabua, Ratlam, Badwani, Burhanpur, Khandwa, Khargone, Alirajpur, Neemuch, Shajapur, Mandsaur and Dewas.
2	Shri Prawendra Kumar Singh, XXI Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Vidisha, Raisen, Hoshangabad, Harda, Rajgarh, Sagar, Betul and Chhindwara.

3	Shri Sushil Kumar Joshi, VIII Additional Sessions Judge, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Datia, Guna, Ashoknagar, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Shivpuri.
4	Shri Vivek Patel, XXI Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Rewa, Shahdol, Umaria, Singrauli, Satna, Katni, Damoh and Sidhi.

This Notification shall come into force with immediate effect.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी. के. द्विवेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.फा. क्र. 2423/21–ब(एक)/2022 भोपाल, दिनांक 29/06/2022

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र क्रमांक ए/974/III–6–3–2018, दिनांक 09.02.2022 के संदर्भ में,
2. महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल,
3. महानिदेशक, मध्यप्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, भोपाल,
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. उप नियत्रंक, केन्द्रीय मुद्रणालय, म.प्र की ओर सूचनार्थ एवं (म.प्र. राजपत्र भाग–एक के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा,विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड़ करने बाबत प्रेषित।

(उमेश पाण्डव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग